ई संदेश

26 मार्च, 2026 | अंक -198

सात दिन, सात पृष्ठ

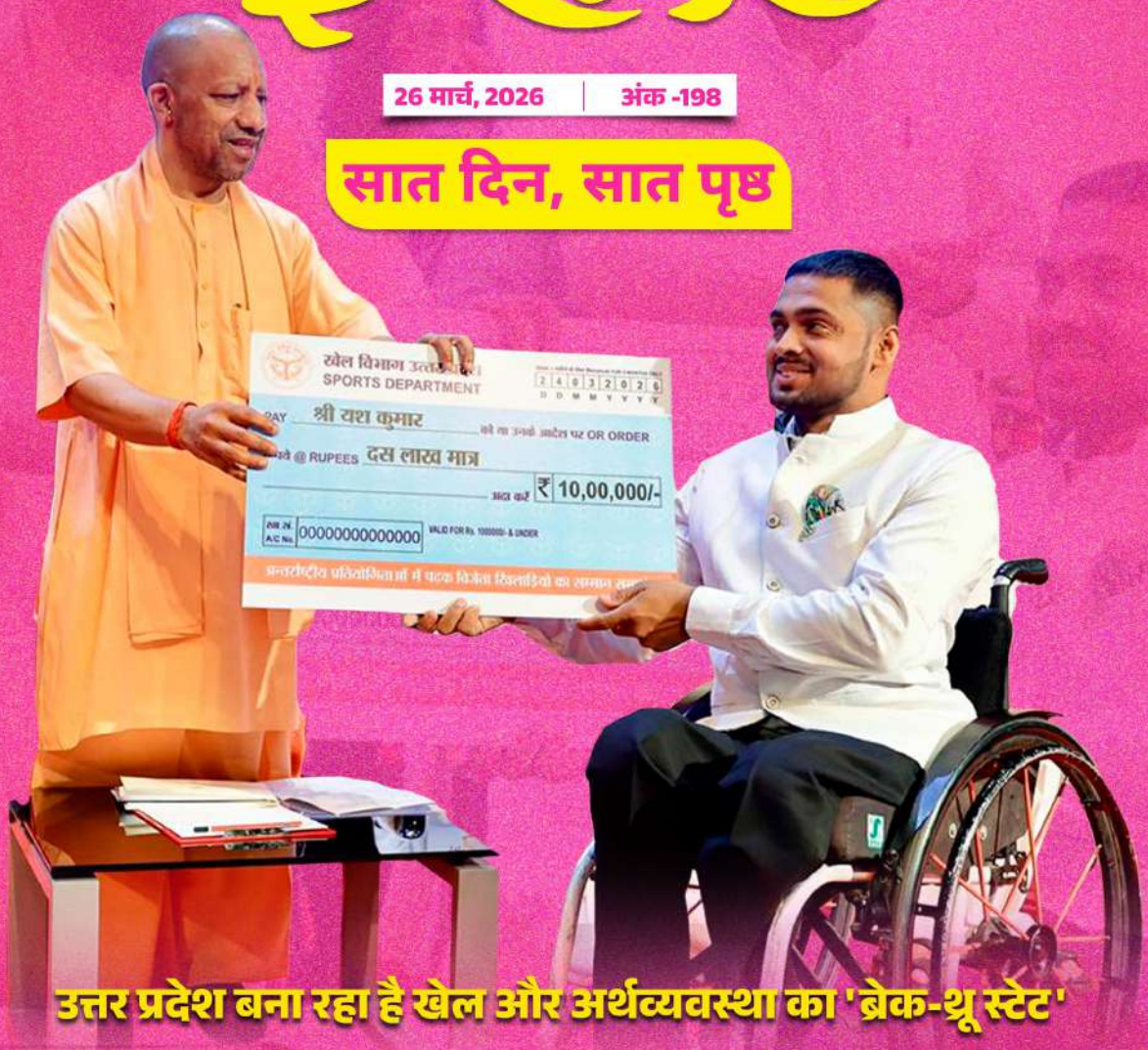

उत्तर प्रदेश बना रहा है खेल और अर्थव्यवस्था का 'ब्रेक-थ्रू स्टेट'

- वन और वन्यजीव संरक्षण से ही सुरक्षित होगा मानव सभ्यता का भविष्य: मुख्यमंत्री
- प्रदेश सरकार का बड़ा संकल्प: आत्मनिर्भर और हाईटेक होंगे गो-आश्रय स्थल, हर गोशाला में बनेगा 'भूसा बैंक'
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'टोयसा' मंच से खिलाड़ियों को सराहा, साझा किया 2036 ओलंपिक का रोडमैप
- नारी शक्ति के स्वावलम्बन से सुदृढ़ होती प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
- विश्वस्तरीय शहरी परिवहन से संवरेगा उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो परियोजनाओं को आत्मनिर्भर और सुगम बनाने के दिए निर्देश
- मुख्यमंत्री ने 'निवेश मित्र 3.0' का किया शुभारम्भ; निवेशकों को 2,781 करोड़ रुपये का इन्सेन्टिव और 50 हजार करोड़ के निवेश हेतु एल0ओ0सी0 प्रदान की
- युवा शक्ति का अनुशासन और परिश्रम ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव, उत्तर प्रदेश बना रहा है खेल और अर्थव्यवस्था का 'ब्रेक-थ्रू स्टेट': मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 23 मार्च, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

वन और वन्यजीव संरक्षण से ही सुरक्षित होगा मानव सभ्यता का भविष्य: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 मार्च, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए वन और प्रकृति के संतुलन को जीवन का मूल आधार बताया। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'वन एवं अर्थव्यवस्थायें' विषयक राष्ट्रीय वानिकी संवाद (अरण्य समागम) का उद्घाटन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वन और जल सुरक्षित हैं, तभी वायु और जीवन की कल्पना संभव है। मुख्यमंत्री ने भारतीय ऋषि परंपरा के उस पावन संदेश 'दशपुत्रो समो द्रुमः' का स्मरण कराया, जिसमें एक वृक्ष को दस पुत्रों के समान पुण्यदायी माना गया है। उन्होंने जनमानस को अपनी जिम्मेदारी का बोध कराते हुए कहा कि 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' के भाव के साथ हमें धरती माता के सम्मान और संरक्षण में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन्य जीव विभाग और वन विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया, जिनमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सुहेलदेव वन्य जीवन अभ्यारण्य और '09 साल बेमिसाल' जैसी कॉफी टेबल बुक्स शामिल हैं। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों, सामाजिक संगठनों और विभाग के कर्मठ अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ-साथ अन्नदाता किसानों को कार्बन क्रेडिट चेक भी प्रदान किए। उत्तर प्रदेश इस दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जिसने मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में शामिल कर प्रभावितों को त्वरित सहायता सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों का विवरण देते हुए बताया कि विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जिसे अब 16 से 17 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड 242 करोड़ वृक्षारोपण की सफलता समाज के जन-आंदोलन बनने के कारण ही संभव हो पाई है। इस वर्ष भी मानसून के दौरान 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत 50 करोड़ पौधे तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चर्चा करते हुए बताया कि जहां प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडीचर कर रहा है, वहीं वनाच्छादन में निरंतर वृद्धि एक सुखद संकेत है।

प्रदेश में ईको-टूरिज्म और जैव विविधता के विस्तार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामसर साइट्स की संख्या 1 से बढ़कर 11 हो चुकी है, जिसे 100 तक ले जाने की कार्ययोजना है। उन्होंने गंगा डॉल्फिन की बढ़ती संख्या और गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र की सफलता को प्रदेश की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। इसके साथ ही, अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के माध्यम से प्रदेश को नेट-जीरो लक्ष्य की ओर ले जाने के प्रयासों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी से अपील की कि आगामी जुलाई माह में 'एक पेड़ मां के नाम' अवश्य लगाएं और 100 वर्ष से पुराने 'विरासत वृक्षों' के संरक्षण के लिए एकजुट हों, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और हरा-भरा भविष्य प्राप्त हो सके।

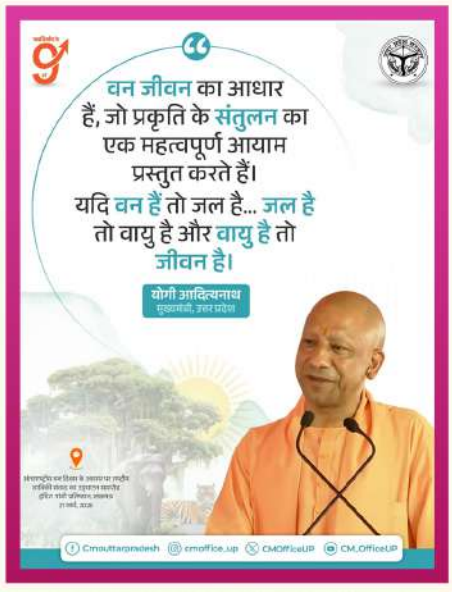

प्रदेश सरकार का बड़ा संकल्प: आत्मनिर्भर और हाईटेक होंगे गो-आश्रय स्थल हर गोशाला में बनेगा 'भूसा बैंक'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 मार्च, 2026 को यहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग की बैठक में निराश्रित गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक गोशाला में 'भूसा बैंक' की स्थापना पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी, तकनीक युक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। इस बैठक का सबसे प्रमुख बिंदु प्रत्येक गोशाला में 'भूसा बैंक' की स्थापना रहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि स्थानीय किसानों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर हरे चारे की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गो-संरक्षण केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक खेती और सतत विकास का एक मजबूत आधार है, इसलिए प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को सीधे इन गो-आश्रय स्थलों से जोड़ा जाए।

प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री ने गो-सेवा आयोग के पदाधिकारियों और पशुधन विभाग के अधिकारियों को नियमित जमीनी निरीक्षण के निर्देश दिए। आयोग के पदाधिकारियों को दो-दो के समूहों में मण्डलवार भ्रमण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो विशेष रूप से 'भूसा बैंक' की स्थापना और गोचर भूमि के विस्तार कार्यों की प्रगति देखेंगे। इन दौरों की विस्तृत रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही, विभागीय मंत्री के नेतृत्व में राज्यव्यापी निरीक्षण और मुख्यालय स्तर से औचक निरीक्षण की व्यवस्था भी लागू की गई है ताकि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता न रहे। मुख्यमंत्री ने गो-आश्रय स्थलों में पारदर्शिता के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध भुगतान और हर केंद्र पर गोवंश की दैनिक संख्या का अनिवार्य रजिस्टर रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश वर्तमान में गो-संरक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश के 7,527 गो-आश्रय स्थलों में वर्तमान में 12.39 लाख से अधिक गोवंश सुरक्षित हैं। इनमें अस्थायी स्थलों, वृहद गो-संरक्षण केंद्रों, कान्हा गो-आश्रयों और कांजी हाउसों का व्यवस्थित नेटवर्क कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत भी 1.14 लाख लाभार्थियों को 1.83 लाख गोवंश सुपुर्द किए गए हैं, जिनका नियमित सत्यापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और निगरानी को आधुनिक बनाने के लिए सभी गो-आश्रय स्थलों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने और इसके लिए सीएसआर फंड का प्रभावी उपयोग करने की बात कही। वर्तमान में 74 जनपदों के 5,446 केंद्रों पर 7,592 कैमरे लगाए जा चुके हैं और 52 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल रूम के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है।

गो-आश्रय स्थलों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में 97 गोबर गैस संयंत्रों का संचालन हो रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा और आय सृजन का माध्यम बन रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गो-अभयारण्य को एक उत्कृष्ट मॉडल बताते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा गो-पेंट, वर्मी कम्पोस्ट और गो-दीप जैसे उत्पादों के निर्माण की सराहना की। इसके अलावा, गोचर भूमि के प्रभावी उपयोग के तहत 61,118 हेक्टेयर भूमि में से बड़ी मात्रा को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ा गया है, जहां हरे चारे का विकास किया जा रहा है। पशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए खुरपका-मुंहपका और लम्पी जैसी बीमारियों के विरुद्ध व्यापक टीकाकरण अभियान भी निरंतर जारी है। अंत में, मुख्यमंत्री ने गो-रक्षा और गो-सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया, ताकि सामाजिक सहभागिता को और बढ़ावा दिया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'टोयसा' मंच से खिलाड़ियों को सराहा साझा किया 2036 ओलंपिक का रोडमैप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 मार्च, 2026 को लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित 'टाइम्स ऑफ इण्डिया स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स' (TOISA) कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने देश की महान खेल विभूतियों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विगत 11-12 वर्षों के दौरान भारत में एक नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि आज खेलो इण्डिया, फिट इण्डिया और राष्ट्रीय खेल नीति-2025 जैसे अभियान धरातल पर उतरकर युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने इस भव्य समारोह में टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएण्डर पेस को 'मेण्टर ऑफ द ईयर', क्रिकेट की दीवार मानी जाने वाली मिताली राज और हॉकी के पूर्व कप्तान पी.आर. श्रीजेश को 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया। खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश को 'टोयसा स्टेट ऑफ द ईयर' के गौरवशाली सम्मान से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम को 'टीम ऑफ द ईयर' व बीसीसीआई को 'फेडरेशन ऑफ द ईयर' के पुरस्कार प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 11-12 वर्षों में भारत में एक ऐसी खेल संस्कृति विकसित हुई है, जहाँ अब खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति-2025, फिट इण्डिया और खेलो इण्डिया जैसे अभियानों ने खिलाड़ियों को वह मंच प्रदान किया है, जिसकी कमी पूर्ववर्ती सरकारों में महसूस की जाती थी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह उनका सौभाग्य है कि वे लगातार तीसरी बार इस प्रतिष्ठित आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, जो टीम भावना और विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।

उत्तर प्रदेश के खेल बुनियादी ढांचे में आए क्रांतिकारी बदलावों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय और विद्यालयों के साथ खेल के मैदान अनिवार्य कर दिए गए हैं। ग्रामीण युवाओं के स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के लिए 'ओपन जिम' अब हर गाँव की प्राथमिकता बन चुका है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के सभी 18 मण्डल मुख्यालयों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जहाँ प्रत्येक कॉलेज में किसी एक विशिष्ट खेल के लिए 'सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस' विकसित होगा।

ये केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाएंगे, जिससे भारत कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 और ओलम्पिक गेम्स-2036 के लिए पदक विजेताओं की एक सशक्त पौध तैयार कर सके।

खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल नीति में ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं। अब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में 500 से अधिक स्पोर्ट्सपर्सन को डिप्टी एसपी और तहसीलदार जैसे राजपत्रित पदों पर नियुक्त किया गया है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी ऊर्जा युवाओं को प्रोत्साहित करने और खेल के विकास में लगा सकें। उन्होंने टोक्यो और पेरिस पैरालम्पिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा, दीपा मलिक और खेल सचिव सुहास एल.वाई. जैसे अधिकारियों व खिलाड़ियों के उदाहरण देते हुए युवाओं से समर्पण की अपील की।

समारोह के दौरान खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. ऊषा, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और खेल जगत की नामी हस्तियां जैसे साइना नेहवाल, रानी रामपाल, दीपा कर्माकर, लक्ष्य सेन और मीराबाई चानू भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने समापन के दौरान कहा कि इन दिग्गजों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में खेल के प्रति अनुराग पैदा करती है और चुनौतियों को अवसर में बदलने का हौसला देती है।

नारी शक्ति के स्वावलम्बन से सुदृढ़ होती प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 मार्च, 2026 को राजधानी लखनऊ में 'मिशन रोजगार' के अंतर्गत आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नर्सिंग को सेवा और संवेदना का पर्याय बताते हुए कहा कि जब एक प्रोफेशनल की दक्षता में मानवीय संवेदना जुड़ती है, तो मरीज के उपचार में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बासंतीय नवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में बेटियों को सरकारी सेवा का अवसर मिलना 'नारी शक्ति' के स्वावलम्बन का एक आदर्श उदाहरण है। आज के इस वितरण में कुल 1,097 महिलाएँ और 131 पुरुष नर्सिंग अधिकारी सम्मिलित हैं, जिन्हें कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और झांसी सहित प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में तैनात किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में आए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 40 से बढ़कर 81 हो गई है और सरकार 'एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज' के साथ-साथ 'एक जनपद, एक नर्सिंग कॉलेज' के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशनल्स को वैश्विक अवसर उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के साथ-साथ देश की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी, तेलुगु, मलयालम और तमिल में भी प्रशिक्षित करें। मुख्यमंत्री के अनुसार, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी-2020 के तहत अब छात्र नर्सिंग की डिग्री के साथ भाषाई डिप्लोमा भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप जैसे देशों में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एसजीपीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान जैसे संस्थान आज टेली-कंसल्टेशन और सिमुलेशन लैब के माध्यम से देश के अन्य राज्यों को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ डॉक्टर अस्पताल का मस्तिष्क होता है, वहीं नर्सिंग स्टाफ उसकी रीढ़ (बैकबोन) की तरह कार्य करता है। प्रदेश में नर्सिंग की 7,000 और पैरामेडिकल की 2,000 सीटों की वृद्धि इस क्षेत्र के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। इसके साथ ही एमबीबीएस की सीटें भी 5,390 से बढ़कर अब 12,700 हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 9.25 करोड़ लाभार्थियों के जुड़ने तथा 14 करोड़ से अधिक आभा आईडी कार्ड जारी होने को प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि बताया।

रोजगार और सुरक्षा के मोर्चे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि विगत 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में मात्र 10,000 महिला कार्मिक थीं, जिनकी संख्या आज बढ़कर 44,000 हो गई है। पुलिस भर्ती में भी बेटियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। अंत में उन्होंने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे अपनी सेवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान दें।

विश्वस्तरीय शहरी परिवहन से संवरेगा उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो परियोजनाओं को आत्मनिर्भर और सुगम बनाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 मार्च, 2026 को लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और उत्तर प्रदेश को आधुनिक व सुगम शहरी परिवहन में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि लखनऊ, कानपुर और आगरा में चल रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए और परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवीनतम वैश्विक तकनीकों का समावेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्माण से लेकर संचालन तक प्रत्येक स्तर पर दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो को केवल आवागमन का साधन मात्र न मानकर इसे शहरों की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजनाओं को दीर्घकाल में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के नए स्रोत विकसित किए जाएं। इसके तहत मेट्रो स्टेशनों और उनके परिसरों में मल्टीलेवल पार्किंग, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट और ऑफिस स्पेस जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा गया है। साथ ही, विज्ञापन, डिजिटल ब्रांडिंग और 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) के माध्यम से राजस्व सृजन के अवसरों को तलाशने के निर्देश दिए गए, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भूमि के मूल्य का अधिकतम लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों को सिटी बस, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं से इस तरह जोड़ा जाए कि यात्रियों को घर से गंतव्य तक निर्बाध यात्रा का अनुभव मिले। इसके लिए लखनऊ, कानपुर और आगरा में अतिरिक्त पार्किंग स्थलों के विकास और फीडर रूटों के निर्धारण पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लखनऊ मेट्रो का विस्तार चारबाग से वसंत कुंज तक वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे पुराने लखनऊ की घनी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, कानपुर मेट्रो के शेष कार्यों को मार्च 2027 तक और आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को जून 2026 तक पूर्ण करने की योजना है।

परियोजना की सफलता का विवरण देते हुए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि तीनों शहरों में मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने 'निवेश मित्र 3.0' का किया शुभारम्भ; निवेशकों को 2,781 करोड़ रुपये का इन्सेन्टिव और 50 हजार करोड़ के निवेश हेतु एल0ओ0सी0 प्रदान की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 मार्च, 2026 को यहाँ लोक भवन, लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 'निवेश मित्र 3.0' पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए निवेशकों को 2,781.11 करोड़ रुपये का इन्सेन्टिव सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किया। साथ ही, 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए 85 लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओ0सी0) एवं पात्रता प्रमाण-पत्र वितरित किये। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 'कौशल कनेक्ट सेल' तथा 'एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल' से संबंधित महत्वपूर्ण एम0ओ0यू0 का भी आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री जी ने 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' तथा डी0बी0एफ0ओ0टी0 मॉडल पर आधारित 'प्लग-एण्ड-प्ले औद्योगिक शेड्स विकास योजना-2026' का भी अनावरण किया।

मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि निवेशकों का विश्वास ही राज्य सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में मात्र 16 एल0ओ0सी0 जारी की गई थीं, जबकि उनकी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद अब तक 3,367 एल0ओ0सी0 जारी कर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जारी किए गए 85 एल0ओ0सी0 के माध्यम से प्रदेश के 50 हजार युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होंगी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अब निवेश केवल एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और पश्चिमांचल सहित प्रदेश के प्रत्येक जनपद में निवेशक अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 'निवेश मित्र 3.0' एक एकीकृत डिजिटल ईको-सिस्टम है, जिसमें 43 विभागों की 530 से अधिक सेवाओं को समेकित कर 200 से कम किया गया है। यह पोर्टल ए0आई0 इनेबल्ड चैटबॉट,

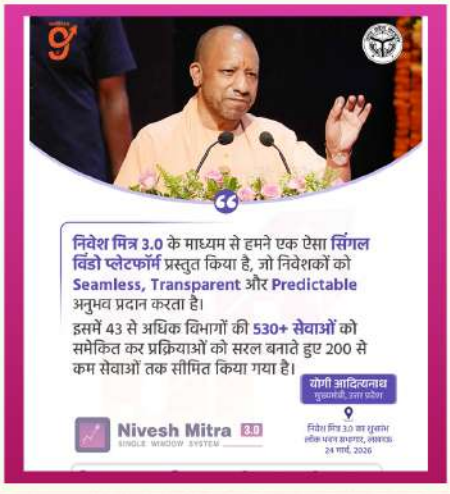

पैन-बेस्ड सिंगल आईडी और रियल टाइम डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं से लैस है, जो निवेशकों को आवेदन से लेकर व्यावसायिक उत्पादन तक 'एण्ड-टू-एण्ड' ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा देगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति ने निवेशकों के मन में सुरक्षा का भाव जगाया है। उन्होंने उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि जब एक उद्योग लगता है तो हजारों परिवारों को आजीविका मिलती है। उत्तर प्रदेश को भारत का 'फूड बास्केट' बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की 11 प्रतिशत कृषि भूमि के साथ उत्तर प्रदेश 21 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते हुए बताया कि देश के कुल एक्सप्रेस-वे का 55 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और आगामी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक्स और कार्गो का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। राजस्व विभाग द्वारा धारा-80 में किए गए सरलीकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब इण्डस्ट्री का मास्टर प्लान ही लैंड यूज सर्टिफिकेट माना जाएगा, जिससे उद्यमियों को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी।

युवा शक्ति का अनुशासन और परिश्रम ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव, उत्तर प्रदेश बना रहा है खेल और अर्थव्यवस्था का 'ब्रेक-थ्रू स्टेट': मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 मार्च, 2026 को यहाँ लोक भवन, लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विशिष्ट खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जब युवा शक्ति अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ती है, तो राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण कार्यक्रम के माध्यम से युवा और नारी शक्ति को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाजा, साथ ही पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि और एकलव्य क्रीड़ा कोष से आर्थिक सहायता का सीधा हस्तांतरण (DBT) उनके बैंक खातों में किया।

मुख्यमंत्री जी ने नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वासन्तीय नवरात्रि के पावन अवसर पर खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देना और सम्मानित करना अत्यंत सुखद है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को नारी गरिमा और स्वावलम्बन का प्रतीक बताया और घोषणा की कि अगले वर्ष से लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि को 3.11 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने विभाग को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहां दैवीय कृपा बरसती है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में 56 प्रतिशत युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। यही कामकाजी वर्ग उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर भारत की अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' और 'रेवेन्यू सरप्लस स्टेट' बना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2014 के बाद देश में एक नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसे अभियानों को अपनाकर प्राचीन खेलों को नया आयाम दिया है। विगत 9 वर्षों में राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। उन्होंने बताया कि अब ब्लॉक स्तर पर 'खेलो इंडिया' केंद्र स्थापित हो रहे हैं और ग्रामीण लीग के माध्यम से गाँवों में खेल के मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार है, जिसका उद्घाटन मई या जून में होगा। साथ ही, हर मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश का नेतृत्व कर सकें।

मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि टैलेंट केवल शुरुआत है, लेकिन मेहनत ही लक्ष्य तक पहुँचाती है। उन्होंने जापान की 'काइज़ेन' (निरंतर सुधार) और 'मोनोज़ुकुरी' (उत्कृष्ट निर्माण) की अवधारणाओं का उदाहरण देते हुए भारतीय ऋषि परंपरा के मंत्र 'योगः कर्मसु कौशलम्' को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक समय खेल के मैदान भू-माफियाओं के कब्जे में थे और बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन 2017 के बाद खेल सरकार की प्राथमिकता बना और बजट में कई गुना वृद्धि की गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों की पुलिस व अन्य विभागों में नियुक्ति हो चुकी है।

आज के कार्यक्रम में क्रिकेट खिलाड़ी रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, राजकुमार पाल व प्रवीन कुमार को डिप्टी एसपी, और अन्य खिलाड़ियों को जिला पंचायत राज अधिकारी व खंड विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त विनय कुमार, विक्रांत बालियान, सागर दांगी और पर्वतारोही दीपक कुमार जैसे अनेक विजेताओं को लाखों रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने अंत में कहा कि मेरठ में बना बैट आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, जो 'लोकल से ग्लोबल' का सटीक उदाहरण है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अनुशासित रहकर परिश्रम की पराकाष्ठा करने का आह्वान किया और विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके सर्वांगीण विकास और सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 23 मार्च, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति कुन्तल के आधार पर रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं का क्रय किया जाएगा। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं क्रय की अवधि 25 मार्च, 2026 से 15 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगी।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगरीय निकायों (नगर निगम को छोड़ते हुए) को विकसित किये जाने हेतु नवयुग पालिका योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। परियोजना की समयावधि 05 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30) तक होगी। इस योजना के अन्तर्गत 58 नगरीय निकाय चयनित किये गये हैं। इनमें 55 नगर पालिका परिषदों (जिला मुख्यालय), 03 नगर पंचायतों (जिला मुख्यालय होने के कारण-नगर पंचायत अकबरपुर जनपद कानपुर देहात, नगर पंचायत ज्ञानपुर जनपद भदोही एवं नगर पंचायत चंदौली जनपद चन्दौली) तथा जनपद गौतमबुद्ध नगर की नगर पालिका परिषद दादरी (जिला मुख्यालय औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने के कारण) को सम्मिलित किया गया है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निजी बिज़नेस पार्क विकास योजना-2025 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। बिज़नेस पार्कों में वैश्विक निगमों हेतु कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, वैश्विक क्षमता केन्द्रों तथा संचालन केन्द्रों की स्थापना के लिए संचालन हेतु तैयार (रेडी-टू-ऑपरेट) एवं प्लग-एण्ड-प्ले सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी, जो सेवा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में तीव्र विस्तार को प्रोत्साहित करेगी।

- मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के अन्तर्गत प्लग-एण्ड-प्ले औद्योगिक शेड्स के विकास हेतु योजना-2026' को स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यू0एस0डी0 1 ट्रिलियन जी0एस0डी0पी0 लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगीकरण की गति बढ़ाने, विनिर्माण क्षमता विस्तार करने तथा औद्योगिक इकाइयों के शीघ्र संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना प्रस्तावित की है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु उपलब्ध विशिष्ट भूखण्ड संख्या-01, सेक्टर कप्पा-02, क्षेत्रफल 174.12 एकड़ भूखण्ड के आवंटन के नियम व शर्तों सहित ब्रोशर के अंतिमीकरण एवं अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रख्यापित कराये जाने तथा उसके प्रतिस्थानी विधेयक के आलेख्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे राज्य विधानमण्डल में पुनःस्थापित/पारित कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 की उपधारा-8 में परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने उक्तानुसार संशोधन के उपरान्त उसके क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसके समाधान हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 की उपधारा-8 में परन्तुक बढ़ा दिये जाने से विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा किसी विनियमित क्षेत्र अथवा किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में गैर कृषिक उद्घोषणा हेतु दोहरी प्रक्रिया का सामना नहीं करना होगा।

- मंत्रिपरिषद ने 'दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0', बागपत की पेराई क्षमता 2,500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 5,000 टी0सी0डी0 करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना हेतु पी0आई0बी0 (पब्लिक इन्वेस्टमेण्ट बोर्ड) द्वारा संस्तुत लागत 37249.89 लाख रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसका वित्तपोषण 50 प्रतिशत राज्य सरकार की अंशपूँजी/अनुदान तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार से ऋण के रूप में किया जाएगा।

- मंत्रिपरिषद ने नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि0 को आवंटित पछवारा साउथ कोल ब्लॉक के विकास हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की समरूपता में, आंकलित लागत 2242.90 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उक्त लागत का वित्तीय पोषण 70 प्रतिशत ऋण (1570.03 करोड़ रुपये) एवं 30 प्रतिशत अंश पूंजी के माध्यम से किया जाएगा।

- मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। विकास क्षेत्र की निरन्तरता एवं सुनियोजित विकास हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में प्रस्तावित इण्टरनेशनल एग्ज़ीबिशन-सह-कन्वेंशन सेण्टर की पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उक्त परियोजना में किसी संशोधन/परिमार्जन की आवश्यकता होने पर मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ स्थित प्राचीन धरोहर भवनों रोशन-उद-दौला व छतर मंजिल को एडाप्टिव रि-यूज़ के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने हेतु भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग को कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित/आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाएगा।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में लखनऊ-हरदोई मार्ग पर दुबग्गा चौराहे पर 03 लेन में फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य (लम्बाई 1811.72 मी0) की सम्पूर्ण परियोजना एवं उक्त कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 30531.37 लाख रुपये (तीन सौ पांच करोड़ इकत्तीस लाख सैंतीस हजार मात्र) के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जिलाधिकारी ललितपुर से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03 फरवरी, 1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवाद स्वरूप नजूल आराजी संख्या 3727/2 रकबा 1.416 हेक्टेयर, जो मौजा ललितपुर परगना, तहसील व जिला ललितपुर के खेवट खाता संख्या 53 नजूल नगर पालिका के खाता संख्या 360 में दर्ज है, इस आराजी में से मात्र 3,250 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क आवण्टित/हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह हस्तान्तरण अपवाद स्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टान्त के रूप में नहीं माना जायेगा।

- मंत्रिपरिषद ने उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग (गैर-पेय में उपयोग) हेतु उत्तर प्रदेश राज्य नीति (सेफ रि-यूज़ ऑफ ट्रीटेड वॉटर पॉलिसी)-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद सम्भल में 24 कोसीय वंशगोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग के नवनिर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य सम्बन्धी परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे के सन्निकट जनपद सम्भल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आई0एम0एल0सी0) की स्थापना हेतु अवस्थापना निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।